महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने जल्द पेराई के लिए मांगा हर्जाना

[जयश्री भोसले | पुणे]

केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार गन्ने की पेराई समय से पहले शुरू करने के लिए राजी हुई महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने प्रति टन की पेराई पर 500 रुपये का हर्जाना मांगा है। मिलों का कहना है कि गन्ने के पूरी तरह तैयार होने से पहले पेराई करने से उससे मिलने वाली चीनी की मात्रा घट जाती है।

आमतौर पर चीनी मिलें दिवाली के बाद पेराई शुरू करती हैं, लेकिन इस वर्ष देश में चीनी का स्टॉक कम होने के कारण दिवाली के निकट इसके दामों में तेजी आने की आशंका के चलते केंद्र सरकार ने शुगर इंडस्ट्री को अक्टूबर की शुरुआत में 2017-18 के सीजन के लिए पेराई शुरू करने का निर्देश दिया है।

इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (ISMA) ने जल्द पेराई के लिए सहमति दी है और अनुमान जताया है कि देश में अक्टूबर में 8 लाख टन चीनी का उत्पादन हो सकता है। इसमें से अधिकतर उत्पादन महाराष्ट्र (3.9 लाख टन) और उत्तर प्रदेश (2.9 लाख टन) में होगा। महाराष्ट्र की चीनी मिलों की एसोसिएशन, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (WISMA) ने फूड मिनिस्ट्री को पत्र लिखकर जल्द पेराई करने से जुड़ी मुश्किलों की जानकारी दी है। पत्र में कहा गया है, 'आमतौर पर पेराई का सीजन दिवाली के बाद शुरू होता है, जब गन्ना तैयार होता है और बरसात का मौसम समाप्त हो जाता है। नवंबर में चीनी की रिकवरी 10-11 पर्सेंट होती है। अगर गन्ने की अक्टूबर में पेराई की जाती है तो यह घटकर 8.5-9 पर्सेंट रह जाती है।' चीनी मिलों का दावा है कि अगर सरकार के निर्देश के अनुसार पेराई पहले शुरू की जाती है उनका चीनी की रिकवरी का पर्सेंटेज 1.5-2 पर्सेंट तक गिर जाएगा और इससे उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर होगी। WISMA के पत्र के मुताबिक, 'पेराई सीजन की जल्द शुरुआत से होने वाले भारी नुकसान की भरपाई अक्टूबर में पेराई किए जाने वाले गन्ने के 500 रुपये प्रति टन के एक इंसेंटिव के साथ की जानी चाहिए।'

प्रति टन ₹500 का हर्जाना

- **गन्ने की** पेराई समय से पहले शुरू करने के लिए राजी हुई महाराष्ट्र की चीनी मिलों ने प्रति टन की पेराई पर 500 रुपये का हर्जाना मांगा है
- **दाम में** तेजी आने की आशंका से केंद्र सरकार ने शुगर इंडस्ट्री को अक्टूबर की शुरुआत में 2017-18 के सीजन के लिए पेराई शुरू करने का निर्देश दिया है

गन्ने से 9 पर्सेंट की चीनी की रिकवरी और 3.9 लाख टन के चीन के प्रॉडक्शन के अनुमान के आधार पर एसोसिएशन ने लगभग 200 रुपये के हर्जाने की मांग की है। महाराष्ट्र की चीनी मिलें जल्द प्रॉडक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं, लेकिन तमिलनाडु की मिलों ने दिवाली पर जरूरत पूरी करने के लिए कच्ची चीनी का इम्पोर्ट करने की अनुमति मांगी है।

Economic Times

18/8/17